

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2025/208

अपील संख्या 129/2025

तारीख रजू 25.11.2025

1. सलीम 2. वहीद 3. अख्तर 4. कमर 5. करामत 6. रहमत 7. फारूख 8. फिरोज खॉ पुत्रान छोटे खॉ समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथू लाल 2. लड्डूलाल 3. सुरेश चन्द पुत्रान रामकुंवार गरोडा समस्त जातियान गरोड्या निवासीयान खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

.....रेस्पोजेन्टान

वकील अपीलान्ट्स

—श्री चिरंजी लाल बैरवा

वकील रेस्पोजेन्टस 1 लगा. 3

—श्री शिवचरण सोनी

निर्णय

दिनांक:— 30.03.2026

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 01/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के तहत खसरा नम्बर 2584, 2585, 2586, 2591, 2594 कुल किता 5 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम खिरनी से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्टान की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेन्टान सं0 1 लगा0 3 की ओर से श्री शिवचरण सोनी एडवोकेट तथा रेस्पोजेन्टान सं0 4 की ओर से परोकार सरकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय विधि विरुद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के पिता छोटे खॉ पुत्र याकूब खॉ ने जरिये इकरारनामा आराजी ख0नं0 2584, 2585, 2586, 2587, 2594 कुल किता 5 कुल रकबा 0.72 है0 को दिनांक 15.06.1995 को रेस्पोजेन्ट से खरीद किया था तथा मुताबिक इकरारनामा की शर्तों के अनुसार मौके पर ले जाकर सीमा बताकर कब्जा संभलाया था तभी से अपीलान्ट



24


अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उक्त आराजीयात पर बतौर काश्तकार काबिज है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर भी गौर नहीं कर विधि से परे जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी पर अपीलान्तगण ने कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं किया है जिन्हें बेदखल किया जावे बल्कि नियमानुसार जरिये इकरारनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त कर काश्त करते चले आ रहे हैं जिन्हें अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्तों को अतिक्रमी मानकर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात को रेस्पोजेन्टान ने अपनी स्वेच्छा से मिन अपीलांट के पिता को जरिये इकरारनामा रूबरू गवाहान बेचान किया गया है और उक्त इकरारनामा जब तहरीर तकमील के वक्त गवाहान से भी अधिनस्थ न्यायालय ने ना कोई बयान लिये और ना ही उनसे पूछताछ की गई अधिनस्थ न्यायालय ने पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर हल्का पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलांट ने रेस्पोजेन्ट की उक्त आराजीयात पर जबरन धमका कर बिना प्रतिफल दिये ही कब्जा कर अतिक्रमण किया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर नहीं कर अपीलान्त के खिलाफ उक्त पारित निर्णय काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्त के पिता ने उक्त आराजीयात को रेस्पोजेन्ट की इच्छा के अनुसार मुताबिक इकरारनामा प्रतिफल प्राप्त कर लिया गया है जिसमें सभी गवाहान के बयान लेखबद्ध किये जाने चाहिए थे। अपीलान्त को रेस्पोजेन्ट ने जब उक्त इकरारनामा तस्दीक किया जब यह जानकारी नहीं थी और ना ही रेस्पोजेन्ट ने बताया कि वह अनुसूचित जाति का सदस्य है बल्कि अपीलांट को रेस्पोजेन्ट ने यह विश्वास दिलाया था कि वह सामान्य श्रेणी अर्थात् जोशी परिवार से है जो अक्सर सामान्य श्रेणी का माना जाता है इस आधार पर अपीलांट ने रेस्पोजेन्ट से उक्त इकरारनामा कर उक्त आराजीयात खरीदी है। बाद में रेस्पोजेन्ट के बदनियती आ जाने के कारण उन्होंने फर्जी दस्तावेज अनुसूचित जाति का तैयार कर धारा 42 (ख) का लाभ लेकर उक्त निर्णय पारित करवा लिया जो विधि सम्मत नहीं हैं क्योंकि उक्त इकरारनामे में गोरोडा शब्द कहीं पर भी नहीं है बल्कि जाति के आगे "जोशी" लिखा हुआ है जो सामान्य वर्ग का द्योतक है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त इकरारनामा का पूर्ण अवलोकन नहीं कर मात्र अनुसूचित जाति का कूटरचित दस्तावेज का मानकर धारा 42 (ख) आर0टी0 का उल्लंघन मानकर उक्त निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने उक्त इकरारनामे के आधार पर एक वाद पत्र उप जिला कलेक्टर मलारना डुंगर के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसका मु0नं0 44/25 तथा टी0आई0 मु0नं0 27/25 बउनवानी सलीम बनाम नाथूलाल वगै0 है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलान्त को उक्त आराजीयात से बेदखल नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक ही पक्ष को ध्यान में रखकर निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह काबिले खारिज किये जाने योग्य है। भारतीय

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

रूढी के अनुसार आज भी ग्रामीण अंचल में जोशी को ब्राहमण ही माना जाता है और इसी आधार पर अपीलान्त के पिता छोटे खॉ ने रेस्पोडेन्ट से उक्त इकरारनामा बेचान से यह आराजीयात जो मद नं0 2 में दर्शायी है खरीदी है परन्तु अपीलान्त को इसकी जानकारी तब हुई जब अपीलान्त रेस्पोडेन्ट से उक्त आराजीयात या मुताबिक इकरारनामा के अनुसार विक्रय पत्र तस्दीक कराने को कहा तब रेस्पोडेन्ट नाराज हो गये और विक्रय पत्र तस्दीक कराने से मना कर दिया और अधिनस्थ न्यायालय में जरिये पोर्टल शिकायत दर्ज कराकर व राजस्व कर्मचारियों से साज कर उक्त कपोल कल्पित निर्णय अपने पक्ष में पारित करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि उक्त आराजीयात से अतिक्रमी अपीलान्त को बेदखल कर कब्जा रेस्पोडेन्ट को सौंपा जाये जबकि न्यायालय ने जो निर्णय करते समय पत्रावली का पूर्ण अवलोकन न कर गहरी भूल की तथा अकारण ही अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर बेदखल की कार्यवाही अमल में लायी गयी है वह विधि सम्मत नहीं है इसलिये उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2025 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

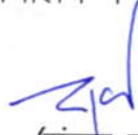
वकील रेस्पोडेन्टान सं0 1 लगायत 3 द्वारा वकील अपीलान्ट्स द्वारा बहस में दिये गये तर्कों का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया है कि विवादित आराजी को अपीलान्त द्वारा रेस्पोडेन्ट से खरीदने का दिनांक 15.06.1995 को लिखा जाना बताया गया है जो प्रारंभ से ही शून्य होने से निरस्त योग्य है तथा शेष इबारत भी मनगढंत एवं गलत दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, उनकी आराजी को अपीलान्त द्वारा खरीदी नहीं जा सकती तथा न ही खरीदने का इकरारनामा ही लिखा जा सकता है। जो धारा 42(ख) का सरेआम उल्लंघन है। अपीलान्त द्वारा गलत आधार पर विवादित इकरारनामा प्रस्तुत किया जिसकी कोई अहमियत नहीं होने से विवादित इकरारनामा को आधार नहीं बनाया जा सकता है। विवादित इकरारनामा शून्य होने से उसमें वर्णित इबारत भी अपने आप में शून्यकरणीय है। विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी कब्जेकाशत की भूमि है जिसमें रेस्पोडेन्ट 1 लगा. 3 ने सरसो की फसल काशत की थी जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा जबरन अतिक्रमण करने पर उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही दिनांक 10.11.2025 को की गई है, जो सही की गई है। विवादित आराजी ख0नं0 2584 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 2585 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 2586 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 2591 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 2594 रकबा 0.31 है0 कुल किता 5 रकबा 0.72 है0 बाके ग्राम खिरनी (ए) तहसील मलारना डूंगर रेस्पोडेन्ट्स की पुश्तैनी आराजी है जो पूर्व में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगा. 3 के पिता रामकुंवार पुत्र श्रीनारायण गरोडा के नाम थी उसके पहले श्रीनारायण पुत्र भूरा गरोडा के नाम दर्ज थी जो पुराने ख0नं0 1878 से बने है। अन्त में वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा. 3 द्वारा अपील अपीलान्त खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।


अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलान्त द्वारा तहसीलदार मलारना डूंगर के मु०नं० 1/25 निर्णय दिनांक 03.11.25 (प्रा०पत्र 183(बी) आर०टी० एक्ट) के विरुद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट न्यायालय हाजा में पेश की है तथा उक्त अपील में यह अंकित किया है कि अपीलान्त द्वारा उक्त आराजीयात जरिये इकरारनामा दिनांक 15.06.95 को रेस्पोजेन्ट्स से खरीद किया था, किन्तु अपीलान्त पत्रावली पर उक्त दस्तावेजात उपलब्ध नहीं करवाये गये। अपीलधीन निर्णय की मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित ख०नं० 2584 रकबा 0.07 है०, ख०नं० 2585 रकबा 0.28 है०, ख०नं० 2586 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 2591 रकबा 0.02 है०, ख०नं० 2594 रकबा 0.31 है० कुल किता 5 रकबा 0.72 है० वाके ग्राम खिरनी (ए) तहसील मलारना डूंगर जमाबन्दी खाता सं० 265 के खातेदार नाथूलाल, लड्डूलाल, सुरेशचन्द पि० रामकुंवार गरोडा (अनु०जाति) के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी ख०नम्बरान पर अपीलान्ट्स सलीम, वहीद, अख्तर, कमर, करामत, रहमत, फारुख, फिरोज पि० छोटे खों के काबिज पाये जाने पर तहसीलदार मलारना डूंगर ने निर्णय दिनांक 03.11.25 के द्वारा उक्त अपीलान्ट्स को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर खातेदार नाथूलाल, लड्डूलाल, सुरेशचन्द पि० रामकुंवार गरोडा को कब्जा संभलाने के आदेश पारित किये गये थे जिसकी पालना में दिनांक 10.11.2025 को सलीम, वहीद, अख्तर, कमर, करामत, रहमत, फारुख, फिरोज पि० छोटे खों को आराजी ख०नं० 2584 रकबा 0.07 है०, ख०नं० 2585 रकबा 0.28 है०, ख०नं० 2586 रकबा 0.04 है०, ख०नं० 2591 रकबा 0.02 है०, ख०नं० 2594 रकबा 0.31 है० कुल किता 5 रकबा 0.72 है० पर मौके पर से बेदखल किया जाकर खातेदार नाथूलाल, लड्डूलाल, सुरेशचन्द पि० रामकुंवार गरोडा को उक्त आराजी का कब्जा मय फसल (सरसों) सहित मौके पर दिनांक 10.11.25 को ही सम्भलाया जा चुका है। रेस्पोजेन्ट्स उक्त आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है तथा वर्तमान में काबिज है। रेस्पोजेन्ट्स द्वारा अनु०जाति का जाति प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त चलने योग्य नहीं पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर